भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1952
08/08/2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

मौसम की बेहद खराब स्थिति से निपटना

1952. श्री संजीव अरोड़ा:

क्या **पृथ्वी विज्ञान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

सरकार ने मौसम की बेहद खराब स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं, जिसके कारण कई शहरों में स्कूल बंद करने पड़ते हैं और बाहर काम करने वाले लोगों के लिए हीटस्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता हैं?

उत्तर
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

भारत मौसम विभाग (आईएमडी) ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), राज्य सरकारों और स्थानीय स्वास्थ्य विभागों के साथ मिलकर देश के अनेक भागों में लू कार्य योजनाएं (एचएपीएस) शुरू की हैं, ताकि लू के बारे में पहले से चेतावनी दी जा सके।

एनडीएमए और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा लू की स्थितियों से प्रभावित 23 राज्यों में लू कार्य योजनाएं तत्काल और दीर्घकालिक कार्रवाई के लिए संयुक्त रूप से लागू की गई हैं, ताकि तैयारियों, सूचना-साझाकरण और प्रतिक्रिया समन्वय को बढ़ाया जा सके, जिससे बाहर काम करने वाले लोगों सहित संवेदनशील आबादी पर अत्यधिक गर्मी के कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को कम किया जा सके। इसके अलावा, आईएमडी ने निगरानी, पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनी प्रणालियों को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिससे लू की स्थितियों सहित चरम मौसम की घटनाओं के दौरान जान-माल के नुकसान को कम करने में मदद मिली है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

i. तापमान तथा लू संबंधी स्थितियों का ऋतुनिष्ठ तथा मासिक आउटलुक जारी करना, उसके पश्चात विस्तारित अवधि पूर्वानुमान जारी करना। पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनियाँ समय पर सार्वजनिक पहुँच के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रसारित की जाती हैं।
ii. भारत की जिलेवार लू सुभेद्यशीलता एटलस, जिससे राज्य सरकार के प्राधिकरणों एवं आपदा प्रबंधन एजेंसियों को योजना बनाने में सहायता मिल सके।
iii. भारत में गर्म मौसम से उत्पन्न होने वाले जोखिमों का विश्लेषण मानचित्र, जिसमें दैनिक तापमान, हवा तथा आर्द्रता की स्थितियां शामिल हैं।
iv. ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत से बहुत पहले राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय लू की तैयारी से संबंधित बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की जाती है। इसके साथ ग्रीष्म ऋतु के दौरान समय-समय पर नियमित समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

****